

दस्तावेज़



निरंकारी मिशन के सत्संग पर हमले के बाद यह मानने में कोई हिचक नहीं है कि पंजाब को ठीक 1980 के दशक के भयावह दौर में ले जाने की साजिशें रची जा चुकी हैं। हमले का स्थान और समय बताता है कि यह बिल्फुल सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। केंद्र सरकार पंजाब और पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियोंके साथ खुफिया एजेंसियों की बैठक बुलाकर पूरी स्थिति का आकलन करे तथा सुरक्षा ऑपरेशन की योजना बनाए।

आतंकी हमला बड़ी साजिश का अंग

देश के जिन लोगों ने 1980 के दशक में पंजाब के भयावह आतंकवाद के दृश्य देखे हैं उनका दिल निश्चय ही अमृतसर के राजासांनी क्षेत्र के अदलीवाल गांव के निरंकारी भवन पर हुए हमले से दहल गया होगा। इसे आतंकवादी हमले के अलावा और कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कोई एक व्यक्ति निशाने पर होता तो हमले को दूसरे नज़रिए से देखा जा सकता था। यहां परा समूह निशाने पर था। गवावार को निरंकारी भवनों में अनुयायी एकात्र होते हैं और सत्संग चलता है। सत्संग के बीच बाइक सवार तीन युवक आएं और बम चलाकर भाग जाएं तो साफ है कि वो निश्चित उद्देश्य के तहत निरंकारी लोगों की हत्या करना चाहते थे। इस घटना में कम लोगों की जान गई और धायल होने वालों की संख्या ज्यादा नहीं थी इस आधार पर इसकी भयावहता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। 1980 के दशक में खालिस्तानी आतंकवादी ऐसे ही बाइकों पर नकाबपोश के रूप में आकर हमले करते थे। इसलिए यह तरीका भी भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है। पंजाब पुलिस अपने बचाव में जो भी तर्क दे लेकिन यह स्थान अमृतसर शहर से केवल सात किलोमीटर दूर है। अमृतसर स्टेशन से इसकी दूरी 13.7 किलोमीटर तथा पाक सीमा से 17-18 किलोमीटर है। इसलिए इसे दूरस्थ गांव नहीं माना जा सकता।

पंजाब पुलिस का अधिकृत बयान है कि उनके पास इस संभावित खतरे को लेकर कोई इनपुट नहीं था। निरंकारी समाज को लेकर किसी भी तरह का मुदवा नहीं था और न ही ऐसा कोई इनपुट पुलिस के पास था। यह बयान स्थिकार्य नहीं है। क्या पुलिस के पास ऐसी सूचना होगी कि फलां संस्थान और फलां जगह हमला होगा तभी उसे सटीक इनपुट माना जाएगा? धार्मिक स्थलों पर हमले का इनपुट तो था। कुछ ही दिनों पहले थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रत्न ने कहा था कि पंजाब में आतंकवादी शक्तिया फिर सिर उठा रही है और तुरत कार्रवाई नहीं की गई तो कठिनाइयां बढ़ जाएंगी। सेना प्रमुख बिना पुष्ट सूचना के इतनी बड़ी बात सार्वजनिक तौर पर नहीं बोल सकते। जाहिर है, पंजाब पुलिस ज्ञात तथ्य को छिपाने का प्रयास कर रही है। हमले के तीन दिनों पहले खबर आई थी कि खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को इनपुट भेजा है कि कश्मीर का खुंखार आतंकी जाकिर मूस अपने साथियों के साथ पंजाब के गास्ते दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पनाह ले सकता है। इनपुट में कहा गया था कि जैश-ए-मोहम्मद के छह सात आतंकवादी हमले की साजिश रच रहे हैं। सीमा पार से छह-सात

आतकवादियों के पंजाब में भुसने की खबर भी थी। जाकिर मूसा के अमृतसर में देखे जाने की खबर आई थी। पंजाब से अचानक उसकी एक तस्वीर वायरल हो गई थी।

खुफिया ब्यूरो को इनपुट मिला था कि जाकिर मूसा गिरोह के सात आतंकी फिरेजपुर आए थे। पठानकोट जिले के माधोपुर के नजदीकी ड्राइवर की हत्या कर एसयवी कार छीनने वाले चार लोग अभी तक फरार हैं। पंजाब पुलिस ने ही बताया था कि ये चार आतंकवादी मंसूबों को अंजाम देने के लिए पंजाब में घुसे हैं। ये चारों सदिग्ध जम्मू रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आए थे। दिल्ली से सुरक्षा एजेंसियों ने पांच सदिग्ध आतंकवादियों की तस्वीरें पंजाब के पुलिस महानिदेशक सुरेश अरोड़ा को मेल की गई थीं। इन सब सचिनाओं के बाद ही पिछले कई दिनों से पंजाब में हाईअलर्ट था। पिछले दिनों जालंधर से शबनमदीप सिंह नामक खतिरिस्तानी आतंकवादी गिरफतार हुआ था। इसने पाकिस्तान की सजिशों के बारे में बताते हुए कहा था कि दीपावली से पूर्व हमले की योजना है। इसके बाद आखिर पुलिसको क्या इनपुट चाहिए थे? जालंधर में ही एक कशमीरी युवक ग्रेनेड के साथ पकड़ा गया था। इतना ही नहीं जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ पंजाब पुलिस ने ग्लाउ ग्री में पंजाब के संचानों में पढ़ रहे कश्मीरी

जाग युक्त उस ने हाल ही न पंजाब का स्थाना न मढ़ रख दिया।
छात्रों के दो गिरेहों का पर्दाफाश किया था, जिनके संबंध कश्मीरी
आतंकी संगठनों से थे। जिन आतंकवादियों के पाकिस्तान से पंजाब
में सड़क मार्ग से फिरोजपुर में घुसने की आशंका थी उनकी तलाश
अभियान चल रहा था।

यह खबर भी लंबे समय से थी कि लंदन से कनाडा तक के
खलिस्तान समर्थक पंजाब में फिर से हिंसा और अशांति की स्थिति पैदा
करने के लिए सक्रिय हैं तथा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई
अपने स्तर पर काम कर रही है। 18 महीनों में स्वयं पंजाब पुलिस ने
15 से ज्यादा आतंकवादी मॉड्यूल को नष्ट करने का दावा किया है। अगर आपने 15 मॉड्यूल पकड़ तो निश्चय ही ऐसे अनेक मॉड्यूल
छिपे हुए होंगे। आतंकियों ने तो बयान जारी कर पंजाब के मुख्यमंत्री
कैप्टन अमरिंदर सिंह एवं सेना प्रमुख जनरल रावत को जान से मारने
की धमकी दे रखी है। इन सबके बाद कैसा इनपुट चाहिए यह समझ
से परे है। 12 अगस्त को लंदन के सिंच्छ फार जस्टिस के बैरन से
2020 सिंच्छ जनमत संग्रह रैली निकाली गई। इसमें खालिस्तानीं
उग्रवादी समूहों के बचे आतंकवादियों को संदेश निहित था कि आप

सक्रिय हो, आपके साथ बड़ा समूदाय खड़ा है। यह अलग बात है कि इनसे बड़ी संख्या में सिखों ने ही लंदन में विरोध में रैली निकालकर कशग्र जवाब दे दिया। किंतु इससे इन दृष्ट समूहों की सक्रियता का पता तो चल गया। इसलिए ऐसे हमले की आशंका नहीं होने के किसी बयान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत विरोधी खालिस्तानी समूह भाड़े के हत्यारों से बीच-बीच में अलग-अलग संगठनों की हत्याएं करवा रहे थे। आरएसएस के नेताओं की हत्या का उद्देश्य यह था कि इससे हिंदू गुरुसे में सिखों से लड़ँ और प्रदेश साप्रदायिक दंगों की चपेट में आ जाए। ठीक यही दृष्टिकोण निरंकारी अनुयायियों पर हुए हमले में भी देखा जा सकता है। बाबा बूटा सिंह द्वारा 1929 में स्थापित निरंकारी मिशन के दुनिया में एक करौड़ से ज्यादा अनुयायी हैं। पंजाब के तरनतास्न, गुरदासपुर, मोगा, लुधियाना, पठानकोट सहित अनेक स्थानों पर निरंकारी अनुयायियों की बड़ी संख्या है। ठीक सत्संग के समय हमला करने का सीधा उद्देश्य यही हो सकता है कि ये गुरुसे में हिंसा आरभ कर दें। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि 40 वर्ष पूर्व 13 अप्रैल 1978 को वैसाखी के दिन अमृतसर में निरंकारी भवन पर हुए हमले के बाद पंजाब हिंसा की चपेट में आ गया था और भिंडारावाले वहीं से एक वर्ग में लोकप्रिय हुआ। हमले के बाद अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ जिसमें 13 अकाली कार्यकर्ता मारे गए थे। इसके विरोध में रोष दिवस मनाया गया। जरनैल सिंह भिंडारावाले ने इसको उग्र रूप दिया और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं।

पंजाब के आतंकवाद पर काम करने वाले कई विद्वान मानते हैं कि अगर वह हमला न हुआ होता तो भिंडियावाले और उसके साथी एक वर्ग के हीरो बनकर नहीं उभरते एवं उस प्रकार के भयावह चरमपंथ का आविर्भाव नहीं होता। तो पंजाब को हिस्सा की आग में झोकने के हात के वर्षों के सारे प्रयासों, आतंकियों से संबंधित इनपुट, गिरफ्तारियां, आतंकवादी मॉड्यूल को विफल करने तथा अंततः निंकारी मिशन के सत्संग पर हमले के बाद यह मानने में कोई हिचक ही नहीं है कि पंजाब को ठीक 1980 के दशक के भयावह दौर में ले जाने की साजिशें रखी जा चुकी हैं। हमले का स्थान और समय बताता है कि यह बिल्कुल सुनियोजित साजिश का हिस्सा है।

■ अवधीश कुमार (वरिष्ठ पत्रकार)

विचार

अब बदलनी होगी
बाल गृहों की छवि

बिहार व उत्तरप्रदेश के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने देशभर के 539 बाल गृहों को बंद कर दिया है। ये सभी गृह अनियमित तरीके से चलाए जा रहे थे। सवाल है कि प्रशासनिक मशीनरी अपनी जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निभाने में विमुख क्यों हो जाती है?



बिहार में यौन उत्पीड़न के सनसनीखेज मामलों के उजागर होने की प्रभाविति में देशभर के बालगहों की जांत के दौरान ह जबकि एक शराफ व्यक्ति उसा जुम भी जुमान वा जेल जाने तक की नौबत पर पहुंच जाता है। उत्तर भारत में हम रेलगाड़ियों के माध्यम से कहीं भी

हान का पृष्ठभूम म दशभर के बालगृहों का जांच के दारान अनियमितताएं सामने आने पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देशभर में कुल 539 बाल गृहों (सीरीआई) को बंद कर दिया है। महाराष्ट्र में 377 बालगृहों को बंद किया गया, जो सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित राज्यों में सर्वाधिक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 78 और तेलंगाना में 32 बालगृह बंद कर दिए गए हैं। बिहार के एक आश्रय गृह में 34 नाबालिंग बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न की घटना सामने आने के बाद मंत्रालय ने अगस्त में राज्यों को अपने सभी बालगृहों की जांच के निर्देश दिए थे। जांच में पाया गया था कि करीब 539 बालगृह नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या पंजीकृत नहीं हैं। सरकार ने भले ही 539 बाल गृहों को बंद कर बच्चों को सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध करा दिया है, मगर क्या जिला प्रशासन के अफसरों की जवाबदेही तय नहीं की जानी चाहिए। जिन जिलों में इस तरह के बाल आश्रय गृह संचालित हो रहे थे, वहाँ के अफसरों ने अब तक संज्ञान कर्यों नहीं लिया।

न अब तक सज्जान पाया नहा लिया। देशभर में दो तरह के बाल गृह हैं। एक वे जो पंजीकृत तो हैं, मगर उनके यहाँ बच्चों के लिए सुविधा तक नहीं है। दूसरे वे जो पंजीकृत नहीं हैं। ऐसे गृहों से बेहतर सुविधा की उमीद तक बेमानी है। बिहार का मामला सामने नहीं आया होता और केंद्र सरकार ने संजीदगी नहीं दिखाइ होती तो ये बाल गृह आज भी बच्चों का शोषण कर रहे होते और हम-आप अपनी जिम्मेदारी से मुँह मोड़े बदरंग तस्वीर पर चौड़े हो रहे होते। इन बाल आश्रय गृहों की सच्चाई सामने आने के बाद सिर्फ राज्य सरकारों और जिला प्रशासन ही नहीं समाज को भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। किसी भी अच्छी या बुरी घटना का सीधा संबंध सबसे पहले समाज से होता है। सरकार व प्रशासन की भूमिका बाद में सामने आती है। अगर इस मसले पर समाज अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभा पाया, तो आश्रय संचालकों को दोष देने से क्या फायदा? केवल कुछ लोगों को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा और न ही यह बहर्दा समाज होगी।

ल रखा है न हाँ उसक प्रैट्रैन में माथा मानक का अधिकार पत्र हासिल है। ऐसे ही तमाम गेरुआ वस्त्रधारी लोग भी अपने भगवे लिबास को ही रेलवे का यात्रा पास मानकर पूरे देश में आते-जाते रहते हैं और न केवल सीटों पर कब्जा जमाए रहते हैं बल्कि प्रवेश व निकासी द्वार पर भी अडे बैठे रहते हैं जिससे ट्रेन में चढ़ने एवं उतरने वालों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार इन्हीं भगवा वस्त्रधारी भिखारियों को चलती ट्रेन में

स काम नहीं चलगा आर न हो यह बुराइ समाप्त होगा।

बिहार और उत्तर प्रदेश में बेसहारा बच्चियों के लिए चलाए जा रहे आश्रय स्थलों से उजागर हुए यौन-उत्पीड़न के मामलों से साफ़ है कि उनके संचालन में ध्रुवावार गहरे पैट बनाए हुआ था। हैरानी की बात यह है कि लंबे समय से इस तरह की गतिविधियां चलने के बावजूद संबंधित सरकारी महकमों और उनके अधिकारियों को उनमें कुछ भी गलत होता नहीं दिखा। सवाल है कि अगर यह सोशल ऑफिट का काम नहीं हुआ होता तो क्या वहां वे गतिविधियां पहले की तरह चलती रहती? किसी गैरसरकारी संगठन के जरिए संचालित उन आश्रय स्थलों की निगरानी और जांच-पड़ताल क्या उन सरकारी महकमों का दायित्व नहीं है, जो उन संस्थाओं को आर्थिक मदद महेया करते हैं?

जारी है। अनियमितता पाए जाने पर उन्हें भी बंद किया जाएगा। बच्चों के अधिकार से खिलाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।

मेनका गांधी, केंद्रीय मंत्री

देशभर के बाल आश्रय गृहों को सिर्फ़ इसलिए मनमानी का अधिकार मिला क्योंकि उन पर सरकारी नियंत्रण नहीं था। प्रशासनिक मशीनरी अपना काम सही ढंग से नहीं निभा रही थी।

विजय विद्वाही, वरिष्ठ पत्रकार

५



सत्यार्थ



एक बार उत्तरी वर्जीनिया में
कुछ युवक भ्रमण के लिए पहुंचे।
घूमते-घूमते जब वे एक स्थान पर
भोजन करने के लिए बैठे, तो उन्हें
एक स्त्री के रोने की आवाज
सुनाई दी। वह जोर-जोर से कह
रही थी- मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़
दो। युवक भोजन छोड़कर उस ओर
दौड़े, जिस ओर से आवाज आ रही
थी। उस स्त्री का बच्चा नदी में
गिर गया था और कोई भी व्यक्ति
उसको निकालने की हिम्मत नहीं
कर रहा था। उस स्त्री ने कहा- आप
संबंधियों से छुड़ा दीजिए, ताकि मैं

वाशिंगटन का साहस

को नदी से निकाल सकं। ये न तो स्वयं कोई प्रयत्न कर रहे हैं और न ही मुझे कुछ करने दे रहे हैं। तभी उन में से एक युवक ने पलक झपकते ही कुछ निश्चय किया और कपड़े उतारकर नदी में कूद गया। वह एक अच्छा तैराक था और लहरों से जूँझ रहा था। वह युवक जान हथेली पर रख बहते हुए बच्चे का पीछा कर रहा था, ताकि बच्चे उसकी पकड़ में आ जाए, पर लहरें बार-बार उसे दूर कर देतीं व बच्चे हाथ से छीनकर ऐसे ले जातीं, जैसे

क बच्चे तक
र निकाल
त्रों से युवक
र का बारंबार
कहा- तुम्हारे
और कभी भी
प्राप्ति बचा कर
है, उसका फल
ही कर सकती
क फैले। बच्चे
गाने वाला यह
दाद में अमेरिका

सी.आर.पाटिल भवन में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन



वर्व पार्षद विनोद पाटिल, चे बर ऑफ मॉर्मस के पूर्व अध्यक्ष परेश पटेल सहित डर्ड के भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। सामाजिक अग्रणी सुधाकर चौधरी ने कहा स्वास्थ्य शिविर में चश्मा शिविर का 600 लोगों ने लाभ लिया। उन्हें निःशुल्क चश्मा उत्तरित किया गया। हृदयरोग स्पेश्यालिस्ट डॉक्टर ने 265 मरीजों की जांच की। वहीं को, ईसीजी, यूरिक एसिड, कन्सल्टन्ट नजीशियन, स्त्री रोग स्पेश्यालिस्ट, बाल ग तज्ज्ञ, न्यूरो फिजिशियन, जनरल व प्रो सर्जन, आर्थरेडिक सर्जन, आंखों डॉक्टर, दांत, शगर विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की। शिविर में कुल 1228 लोग शामिल होकर शिविर का लाभ उठाया। बाबा मेमोरियल अस्पताल, मेरिया नगर नवागाम की टिम का शिविर में सहयोग मिला। सामाजिक अग्रणी सुधाकर चौधरी द्वारा हर वर्ष सामूहिक विवाह, रक्तदान समेत कई लोकपयोगी कार्य किए जाते हैं। रविवार को हुए निःशुल्क शिविर में लिंबायत डॉक्टर एसोसिएशन के प्रमुख डॉ. डॉ. नरेंद्र पाटिल, डा. महाले, डॉ. अशोक देवरे, डॉ. वाघ, गणेश पाटिल, डा. भरत पाटिल, डा. उदय पटेल, डा. विजय पाटिल समेत डॉक्टर उपस्थित रहे।

रह हुई परीक्षा के
उम्मोदवारों को
उचित मुआवजा
मिले : कांग्रेस
विधायक

अहमदाबाद। ऊँझा से कांग्रेस की विधायक डॉ. आशा पटेल ने रद्द हुई एलआरडी परीक्षा के उ मीदवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। डॉ. आशा पटेल ने कहा कि परीक्षा देने के लिए दूर दूर से युवक समय और पैसा खर्च कर परीक्षा केन्द्रों पर पहुंचे थे। लेकिन पर्चा लीक होने की वजह परीक्षा रद्द कर दी गई, जिसका खामियाजा उ मीदवारों को भुगतना पड़ा। सरकार और परीक्षा बोर्ड की लापरवाही के चलते परीक्षा रद्द होने से उ मीदवारों को समय बर्बाद हो गया। सरकार उनका समय तो नहीं लौटा सकती है, लेकिन परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचने में जो खर्चा हुआ है, उसका उचित मुआवजा सभी उ मीदवारों को दिया जाना चाहिए। साथ ही भविष्य में जब कभी भी एलआरडी परीक्षा हो तो तब संबंधित उ मीदवारों के लिए उनके निकट के जिले में परीक्षा केन्द्र की व्यवस्था की जानी चाहिए।

राजस्थान में मतदान करे के लिए सूरत में रह रहे प्रवासियों के लिए बुक हुई 60 से ज्यादा बसें



सूरत। राजस्थान में वोटिंग की तारिख जेसे जेसे नजदिक आती जा रही है वैसे ही सूरत में रहने वाले राजस्थानी कपड़े के व्यापारियों में वोटिंग को लेकर उत्सुका बढ़ती जा रही है। अलग-अलग पार्टीयों के उम्मीदवार सूरत में रहने वाले राजस्थानी समाज के तैयारी कर रहे हैं। 7 दिसम्बर को राजस्थान जाने के लिए बसों की बुकिंग की जा चुकी है। जिसमें बाड़मेर, पोकरण, बालोतरा, शिव और जेसलमेर के लिए कुल 60 से ज्यादा बसों को बुक किया गया है। राजस्थान में मतदान के लिए समाज में हुई बैठक उम्मीदवारों को विजई बनाने के लिए जी तोड़ महनत कर रहा है। राजस्थानी कपड़ों के व्यापारी मानसिंह सोढा और अनुप सिंह भाटी ने बताया कि वैष्णव समाज की बाड़ी में राजस्थान मतदान के लिए समाज की मीटिंग होगी जिसमें और कितनी बसों को

लोगों से सम्पर्क कर रहे हैं। राजस्थानी समाज ने बुक करना है इसकी चर्चा
ये लोग राजस्थान जाने की मीटिंग कर अपने अपने की गई।

स्टच्यू आफ यूनिटा का 1 महान में 6 कराड़ का आय
सूरत। दक्षिण गुजरात में नर्मदा बांध के निकट बनी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टच्यू ऑफ यूनिटी दुनियाभर में आकर्षण का केन्द्र बन गई है। 31 अक्टूबर 2018 को स्टच्यू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण के बाद से दुनियाभर के सैलानियों का तांता लगा हुआ है। लोकार्पण के बाद दीपावली अवकाश होने से स्टच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार करनेवालों की लंबी लंबी कतरें लगी। दिवाली की छुट्टियों के दौरान बड़ी सं या में लोग स्टच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार करने पहुंचे। एक महीने के भीतर ढाई लाख से भी अधिक सैलानियों ने स्टच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार किया, जिससे सरदार वल्लभभाई पटेल एकता ट्रस्ट को करेंगे की आय हड्ड है।

दान की रकम वापस मांगने पर योग स्कूली बच्चों ने दिया एडस
गुरु ने किया आत्महत्या का प्रयास जागरूकता का संदेश

सूरत। कामरेज के पारडी आश्रम के योग गुरु प्रदीप ने साधकों द्वारा दान की रकम वापस मांगे जाने पर आत्महत्या की कोशिश की। इससे पहले प्रदीप ने सात पत्रों की स्यूसाइड नोट लिखी थी। जिसमें 10 साधकों के नाम का उल्लेख है।

प्रदीप का आरोप है कि साधक दान में दी गई रकम वापस मांग रहे थे। साधकों की पठानी वसूली से परेशान होकर आत्महत्या करने का फैसला किया था। योग गुरु ने स्यूसाइड नोट में कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। जिसमें लिखा है कि उहोंने पार्डी में संस्था के मकान के लिए जमीन खरीदी थी, जिसकी आधी रकम कई साधकों ने उधार दी थी। रकम इस शर्त पर थी कि सुविधा होने पर रुपए वापस किए जाएंगे। इसके बावजूद कई साधकों मौजूदा स्थिति के लिए जि मेदार ठहराया है।

दूसरी ओर साधकों का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप आधारहीन हैं। एक करोड़ जितनी रकम लौटानी नहीं पढ़े, इसलिए योगगुरु प्रदीप नौटंकी कर रहे हैं। साधकों का कहना है कि योगगुरु प्रदीप ने उधार लिए रुपए जारी वर्ष की दीपावली से पहले देने का वादा किया था। दिवाली से पांच दिन पहले प्रदीप ने उन साधकों को फोन कर बलाया, जिनसे रुपए उधार लिए

बार काउंसिल में वेल्फेर फंड
की रिन्युअल फीस में कटौती

अहमदाबाद । गुजरात राज्य में वकीलों की मौत या निधन के मामले में बार काउंसिल ऑफ गुजरात द्वारा उनके परिजनों या उत्तराधिकारियों को मौत सहायता की रकम दी जाती है और इसके लिए वेल्फेयर फंड स्कीम के तहत फिलहाल मौत सहायता के तहत वकीलों के परिजनों या उत्तराधिकारियों को तीन लाख रुपये की सहायता दी जा रही है । जो १.४.२०१९ से मौत सहायता की रकम चार लाख होने जा रही है अब यह वेल्फेयर फंड स्कीम के तहत वकीलों को समय-समय पर अपना सदस्यपद रिन्यु भी कराना होता है, जिसकी रिन्युअल फीस अभी तक २५०० रुपये थी लेकिन वकीलों में विशेष करके जुनियर वकीलों की मांग को ध्यान में लेकर गुजरात बार काउंसिल द्वारा एक महत्व के निर्णय में वेल्फेयर फंड स्कीम की रिन्युअल फीस में उल्लेखनीय कटौती की गई है । जिसके अनुसार, बकालत के पांच वर्ष पूरा नहीं किया हो ऐसे जुनियर वकीलों को अब सिर्फ एक हजार रुपये रिन्युअल फीस चुकानी पड़ेगी । बार काउंसिल के इस निर्णय की वजह से राज्यभर के वकीलों में खुशी की लहर फैल गई यह गुजरात बार काउंसिल के चेयरमैन दिपेन दवे, पूर्व चेयरमैन अनिल सी.केळा और एकजीव्युटीव कमिटी के चेयरमैन करनसिंह बी. बाघेला ने बताया है । उन्होंने आगे बताया है कि, बार काउंसिल ऑफ गुजरात की रविवारों को हुई एडमीनिस्ट्रेटीव कमिटी की बैठक में रिन्युअल फीस में कटौती करने का निर्णय लिया गया है । जिसके अनुसार जुनियर वकीलों के लिए १००० रुपया किया गया है, इसके अलावा बकालत में एक से १५ वर्ष पूरा किया हो ऐसे वकीलों के लिए वार्षिक १५०० रिन्युअल फीस, १५ से २० वर्ष से प्रेक्टिस करते वकीलों के लिए २००० रुपये और २० वर्ष से ऊपर की प्रेक्टिसवाले वकीलों के लिए २५०० रुपये की रिन्युअल फीस निश्चित की गई है ।

थे। जहां शांतिपूर्वक बातचीत हुई और बाद में जब साधकों ने अपने रूपयों की मांग की, तब प्रदीप ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं। बता दें कि योगगुरु प्रदीप सत्यम फाउंडेशन योगधाम चलाते हैं। साथ ही निःशुल्क योग शिविरों का आयोजन करते हैं और बड़ी संख्या में योगगुरु प्रदीप के साधक हैं।

सूत्रों के मुताबिक पास कार्यकर्ता माइकल योगगुरु प्रदीप को ब्लैकमेल कर रहा था। इसकी जानकारी योगगुरु प्रदीप ने पुलिस को दी है। स्यूसाइड नोट में दस साधकों के नामों का उल्लेख है, जिसमें पास कार्यकर्ता माइकल भी शामिल है। माइकल पास नेता हार्दिक पटेल का करीबी है और सूरत पास टीम का अग्रणी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

A wide-angle photograph capturing a large assembly of students, predominantly girls in white blazers and red-and-white checkered skirts, and boys in various casual and formal attire. They are gathered in a dense crowd outdoors, facing towards the left side of the frame where a man with a mustache, wearing a light-colored plaid shirt, is speaking into a handheld microphone. The scene suggests a school event or a public address.

सूरत। पूरे विश्व में एक दिसम्बर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीते दिन शनिवार को पांडेसरा के गंगोत्री नगर स्थित गौरव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्कूली विद्यार्थियों के साथ जाग्रत मानव दल के कार्यकर्ताओं ने विश्व एड्स को मनाया। इस मौके पर गौरव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के ट्रस्टी विजय कुमार यादव ने कहा कि स्कूली बच्चे देश के भविष्य हैं। शिक्षकों का काम बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं बल्कि उन्हें सामाजिक ज्ञान देने की नैतिक जिमेदारी है। बच्चे एड्स पीड़ितों का उपेक्षा न कर उनके

सम्मान करें। जाग्रत मानव दल के प्रमुख शैलेन्द्र निगम ने कहा कि बच्चे एडस ग्रसित लोगों से परहेज न कर उन्हें उचित सम्मान देने के साथ उनका हर सम्भव मदद करे। इस मौके पर प्रबन्धन समिति मंत्री रीता वी.यादव संजय शुक्ला, अम्बिका मिश्रा, अरविंद द बे संतोष द बे.राजाराम तिवारी, दिनेश गुप्ता, नारायण पांडे य, राजन मिश्रा, पंकज सोनी, शनि तिवारी, रँकी सिंह हार्दिक सिंह, रितेश गुप्ता प्रिंसिपल अमरजीत पांडे य नंदनी गुप्ता, दुर्गेश मिश्रा, संतोष मिश्रा, शैला मिश्रा, किरण सिंह, अंकित जायसवाल, ममत सिंह, शैलेन्द्र आदि मौजूद रहे

नलिया-कंडला एयरपोर्ट में तापमान १३

डिग्री से भी कम
अहमदाबाद । अहमदाबाद
सहित राज्यभर में अब ठंडी का
अनुभव हो रहा है । आज राज्य
के बहुत से इलाकों में न्यूनतम
तापमान शनिवार की तुलना में
और अधिक गिरने से ठंडी बढ़
गई है । आज नलिया में न्यूनतम
तापमान घटकर १२.८ डिग्री
दर्ज हुआ । कंडला एयरपोर्ट में
तापमान गिरकर १२.२ डिग्री तक
पहुंच गया । अहमदाबाद शहर में
तापमान १५ डिग्री रहा । डिसा में
१३.४ और गांधीनगर में १४.४
डिग्री तापमान रहा । तापमान
में और भी अधिक गिरावट हो
सकती है और इससे ठंड का
प्रभाव बढ़ने के संकेत नजर
आ रहे हैं । हवामान विभाग के
अनुसार आने वाले दो तीन दिनों
में लघुतम तापमान में कटौती
नहीं होगी ।

पर्चा लीक होने से एलआरडी की परीक्षा रद्द, मामले की जांच शुरू

सूत्र। गुजरात पुलिस महकमे में लोक रक्षक दल (एलआरडी) के 9 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए रविवार को दोपहर तीन बजे ली जानेवाली परीक्षा रद्द कर दी गई। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष विकास सहाय के मुताबिक पर्चा लीक होने की उन्हें जानकारी मिली है, जिसे ध्यान में रखते हुए परीक्षा फिलहाल रद्द कर दी गई है। सरकार ने गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। एलआरडी के 9713 पदों पर भर्ती के लिए राज्यभर से 876356 परीक्षार्थियों ने फार्म भरे थे। राज्य के 29 शहर व जिलों की 2440 स्कूलों में परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे। पैने लाख से भी ज्यादा उमीदवार 200 से 300 किलोमीटर की यात्रा कर आज सुबह से अपने अपने परीक्षा केन्द्रों पर पहुंचने लगे। लेकिन परीक्षा रद्द किए जाने की खबर से परीक्षार्थियों में सरकार के खिलाफ आक्रोश भड़क उठा। परीक्षार्थियों ने घटना के लिए सीधे तौर पर सरकार को जि मेदार ठहराते हुए हर्जा-खर्चा देने की मांग की है। इस बीच सायबर सेल गांधीनगर जिला पलिस और सीआरडी क्रॉस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक पुलिस ने एक महिला को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है।

निजी अस्पतालों में सी-सेक्शन से प्रसव की संख्या अधिक हैं

अहमदाबाद। भारत में एक साल में निजी अस्पतालों में हुए ७० लाख प्रसवों में से नौ लाख प्रसव बगैर पूर्व योजना के सीजेरियन सेक्शन (सी-सेक्शन) के जरिए हुए जिन्हें रोका जा सकता था और ये ऑपरेशन मुख्यतः पैसा कमाने के लिए किए गए। भारतीय प्रबंधन संस्थान-अहमदाबाद (आईआईएम-ए) ने एक अध्ययन में यह कहा है। शिशुओं के चिकित्सीय रूप से अनुचित ऐसे जन्म से ना केवल लोगों की जेब पर बोझ पड़ता है बल्कि इससे स्तनपान कराने में देरी हुई, शिशु का वजन कम हुआ, सांस लेने में तकलीफ हुई। इसके अलावा नवजातों को अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ा।

वैज्ञानिक टेस्ट कराने के लिए पुलिस की साजिश से विवाद

अहमदाबाद । कलोल में पत्री की आत्महत्या के लिए उकसाने और इसकी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में एक नया मोड़ आया है । कलोल तहसील पुलिस ने तहसील पुलिस, एफएसएल बॉड्यरेक्टर, गृहविभाग सहित वंश सरकार के संबंधित शासकों के महत्व की कानूनी नोटिस भेजकर स्पष्ट सूचना दी गई है । प्रस्तुत केस में सुप्रीम

आरोपी पति के पांच दिन का और रिमांड मांगा इसमें एक कारण आरोपी के पोलीग्राफिक और एसटीएस टेस्ट कराने की वजह से इसका रिमान्ड जरूरी होने का बताया गया। थर्ड एडिशनल सीविल न्यायाधीश और ज्युडीशियल मेजिस्ट्रेट फर्स्टक्लास ए.एम. शुक्ल ने आरोपी का रिमान्ड दे दिया। जिसकी वजह से रिमान्ड के दायरे में पुलिस आरोपी पति कोर्ट के शेल्वी विरुद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटक के २०१० (७) एस्सीसी पेज नंबर-२६३ फैसले के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दर्शायी गई प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई भी परिस्थिति में आरोपी पति के वैज्ञानिक टेस्ट नहीं करना चाहिए। अन्यथा यह सभी शासकों विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भंग और अदालत की अवमानन की कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई थी।

के वैज्ञानिक टेस्ट बाहर ही बाहर एफएसएल में नहीं करा दे इसके लिए वरिष्ठ वकील आरजे. गोस्वामी द्वारा कलोल कलोल के पंचवटी क्षेत्र में संस्कृति बंगले में रहते संदीप प्रवीणभाई पटेल (मूल वतन बोरीसना) की शादी २००२ में

शीतलबहन के साथ हुई थी । शादी में उनको दो संतान थे । संदीपभाई नागरिकों को विदेश भेजने के व्यवसाय के साथ जुड़े हुए थे, जिसमें पिछले कई दिनों में कर्जा हो जाने से अपनी पत्नी को माइक्रो से पैसे की मदद लाने के लिए कहा था लेकिन वह नहीं ला सकने से अक्सर शारीरिक मानसिक रूप से परेशान किया जाता था और इस मामले में अखिर में गत महीने में नर्मदा नहर में कूदकर पत्नी शीतलबहन ने आत्महत्या कर ली यह शिकायत में आरोप लगाया गया है । यह अपराध में पहले कलोल के एडिशनल सीनियर सीविल न्यायाधीश और ज्युडीशियल मेजिस्ट्रेट डी.एस. ठाकर ने आरोपी पति के सात दिन का रिमांड मंजूर किया गया ।